



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264112
CG-DL-E-25062025-264112

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/ आषाढ़ 3, 1947

No. 172]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ ASADHA 3, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून 2025

मामला सं. सीवीडी (एसएसआर) – 01/2025

विषय : मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टैक्सचर्ड टैंपर्ड कोटिड एवं अनकोटिड ग्लास के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की जांच की शुरुआत।

- फा.सं. 7/10/2025-डी.जी.टी.आर.—बोरोसिल रिन्युएबल लिमिटेड (बीआरएल) और विशाखा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड (वीजीपीएल) (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" के रूप में भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीरोधी वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे

इसके बाद "सीवीडी नियम" अथवा "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, मलेशिया (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टैक्सचर्ड टेंपर्ड कोटिड एवं अनकोटिड ग्लास" (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के विस्तार और वृद्धि की शुरुआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

क. विगत जांचों की पृष्ठभूमि

2. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल सब्सिडीरोधी जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच शुरुआत अधिसूचना संख्या 6/13/2019-डीजीटीआर के अनुसार दिनांक 12.09.2019 को आरंभ की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/13/2019-डीजीटीआर दिनांक 11.12.2020 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश की। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को पांच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 09.03.2021 की अधिसूचना संख्या 03/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के अनुसार क्रियान्वित किया गया। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 08.03.2026 तक लागू है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद अधिकतम 4.2 मिमी (0.2 मिमी की टालरेंस सहित) मोटाई वाला न्यूनतम 90.5 प्रतिशत ट्रांसमिशन सहित सख्त बनावट (टेंपर्ड) वाला ग्लास है और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी. से अधिक है, चाहे वह "कोटिड हो या अनकोटिड" (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) संबद्ध वस्तु में अपेक्षित ट्रांसमिशन के न्यूनतम स्तर को आयरन तत्व को निम्न, आम तौर पर 200 पीपीएम से कम पर रखने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ट्रांसमिशन स्तर को लगभग 2 प्रतिशत – 3 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है जब इसे एंटी – रिफ्लेक्टिव कोटिंग लिक्विड से कोटिड किया जाता है। ग्लास चाहे वह कोटिड हो या अनकोटिड, को एक टेंपरिंग फर्नेस में टेंपर्ड / कठोर किया जाता है क्योंकि यह सौर अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य है। उत्पाद को बाजार की भाषा में विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे सोलर ग्लास, लो आयरन सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेंपर्ड लो आयरन पैटर्नड सोलर ग्लास आदि।
4. संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग सोलर फोटोवोल्टिक और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में संघटक के रूप में किया जाता है। ट्रांसमिशन के स्तर को आयरन कंटेंट को निम्न आमतौर पर 200 पीपीएम से कम पर रख कर प्राप्त किया जा सकता है। ट्रांसमिशन स्तर 2 प्रतिशत – 3 प्रतिशत तक बढ़ जाता है जब इसे एंटी – रिफ्लेक्टिव कोटिंग द्रव्य से कोटिड किया जाता है। ग्लास चाहे वह कोटिड हो या अनकोटिड, को एक टेंपरिंग फर्नेस में टेंपर्ड / कठोर किया जाता है क्योंकि यह सोलर अनुप्रयोगों के लिए जरूरी है। इन अनुप्रयोगों में प्रयुक्त ग्लास वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार 2 मिमी. से 4 मिमी. मोटाई तक का है। संबद्ध वस्तुओं का आकार उद्देश्य और माड्यूल आकार पर निर्भर करता है। ग्लास को टेंपरिंग से पहले या कोटिंग के बाद ग्राहक की जरूरत के अनुसार विभिन्न आकारों में काटा जाता है। चूंकि, यह निर्णायक समीक्षा जांच है, उत्पाद वही बना रहेगा जैसा कि अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किया गया था।
5. संबद्ध वस्तुओं को शीर्ष 70071900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं को विभिन्न अन्य टैरिफ शीर्षों जैसे 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 आदि के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया गया है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद विवरण सभी परिस्थितियों में अभिभावी रहेगा।
6. आवेदक ने कोई पीसीएन प्रस्तावित नहीं किया है।
7. तथापि, वर्तमान जांच से संबंधित पक्षकार जांच की शुरुआत की सूचना के प्राप्त होने के परिचालित होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियां उपलब्ध करा सकता है और पीसीएन प्रस्तावित (औचित्य सहित) यदि कोई हो, कर सकता है। औचित्य के बिना किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ग. समान वस्तु

8. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं समान वस्तु हैं। संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टेक्सचर्ड टफेंड (टेंपर्ड) ग्लास और संबद्ध देश से आयातित ग्लास अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विशिष्टताओं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

9. नियम 2 (ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों का हिस्सा नहीं समझा जाएगा।

10. आवेदन मै० बोरोसिल रिन्युएबल्स लिमिटेड (बीआरएल) और मै० विशाखा रिन्युएबल्स लिमिटेड (वीआरएल) द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अतिरिक्त, भारत में तीन अन्य उत्पादक हैं अर्थात् गोर्विंद ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, त्रिवेणी रिन्युएबल्स प्रा० लि०, गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास लि०, जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन आरंभ किया था।
11. आवेदकों ने सत्यापित किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है।
12. जांच दल की प्रथमदृष्ट्या राय यह है कि आवेदक घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग स्थापित करते हैं जैसा कि सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 2 (ख) के तहत परिभाषित किया गया है और आवेदन सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) की अनिवार्यताओं को पूरा करता है।

ड. सब्सिडी कार्यक्रम

13. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक / निर्यातक ने संबद्ध देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई सब्सिडी से लाभान्वित होते हैं जिनमें विभिन्न प्रोविन्सों और नगर निगमों की सरकारें, जिनमें उत्पादक / निर्यातक स्थित है और अन्य सार्वजनिक निकाय शामिल हैं। आवेदकों ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों के संगत कानूनों, नियमों और विनियमों और अन्य अधिसूचनाओं का आश्रय लिया है जोकि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

14. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा मलेशिया की सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदान की गई बड़ी संख्या में जारी सब्सिडीज से लाभ उठाना जारी है जैसाकि नीचे सूचीबद्ध किया गया है। कथित सब्सिडीज में निधियों का सीधा हस्तांतरण और निधियों या देयताओं का संभावित सीधा हस्तांतरण शामिल है, सरकारी राजस्व जो अन्यथा रूप से देय है, को छोड़ दिया जाता है या एकत्र नहीं किया जाता है, उचित पारिश्रमिक से कम पर वस्तु और सेवाओं का प्रावधान आदि शामिल है।

I. अनुदान के रूप में चिन्हित स्कीमें

- i. प्राकृतिक गैस में सब्सिडी
- ii. बाजार विकास अनुदान

II. कर प्रोत्साहनों के रूप में चिन्हित स्कीमें

- iii. अग्रणी स्थिति
- iv. निवेश कर नीतियां
- v. पुनर्निवेश भत्ता
- vi. त्वरित पूंजी भत्ता
- vii. हरित वित्त सहायता पहलें
- viii. निवल ऊर्जा मीटरिंग (एनईएम) और सौर प्रोत्साहन
- ix. क्षेत्रीय प्रोत्साहन (सभा/मेलाका)
- x. आपूर्ति शृंखला सुविधा कार्यक्रम
- xi. सामूहिक राहत
- xii. औद्योगिक निर्माण भत्ता (आईबीए)
- xiii. संयंत्र और मशीनरी के लिए भत्ता
- xiv. मलेशियाई ब्रांड के प्रचार के लिए दोहरी कटौती
- xv. ईस्ट कॉस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में विनिर्माण और विनिर्माण सेवा संबंधी के लिए प्रोत्साहन
- xvi. आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क की वापसी
- xvii. बिक्री कर छूट
- xviii. विनिर्माण गतिविधियों को आउटसोर्स करने के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
- xix. फालतू हिस्से पुर्जों और उपभोज्य वस्तुओं पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
- xx. मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
- xxi. कच्चे माल/घटकों पर आयात शुल्क से छूट
- xxii. निर्यातों के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
- xxiii. निर्यात कार्गो के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
- xxiv. बड़े हुए निर्यात के लिए भत्ता
- xxv. मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए कर छूट

15. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त स्कीमें सब्सिडी प्राप्त हैं क्योंकि इनमें संबद्ध देश या अन्य क्षेत्रीय सरकारों अथवा ऐसे संबद्ध देश की स्थानीय सरकारों, जिनमें सार्वजनिक निकाय शामिल हैं और जो प्राप्तकर्ता (ओं) को लाभ प्रदान करते हैं, से वित्तीय अंशदान प्राप्त करना शामिल है। उन पर कुछ विशिष्ट उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/या कुछ विशिष्ट उत्पादों और / या क्षेत्रों तक सीमित होने का भी आरोप है और इसलिए ये विशिष्ट और प्रतिसंतुलनकारी हैं। कुछ मामलों में उन पर आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं के प्रयोग पर निर्भर होने और / या निर्यात निष्पादन पर निर्भर होने का भी आरोप है।
16. उत्पादकों / निर्यातकों को किसी अन्य सब्सिडी स्कीम के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है जो संभवतः उनके द्वारा प्राप्त की गई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सब्सिडीज की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जो जांच की अवधि के दौरान मौजूद पाई गई हो और जिनका जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा लाभ प्राप्त किया गया हो।

च. सब्सिडी और क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति की संभावना

17. इस बात के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं जो सब्सिडीरोधी शुल्क के वापिस लिए जाने की स्थिति में सब्सिडीकरण के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति की संभावना की ओर संकेत करते हैं। यह कारकों पर आधारित है जैसे आयातों के विपरीत कीमत प्रभाव, जिसमें घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से निम्न पर विक्रियां शामिल हैं, उत्पादन क्षमता का कम उपयोग, गिरती हुई लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर कम आय और घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन और व्यवहार्यता पर संभावित नकारात्मक प्रभाव यदि वर्तमान सब्सिडीरोधी उपायों को समाप्त कर दिया जाता है।

छ. जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, सब्सिडीकरण के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की पुष्टि करते हुए, प्राधिकारी, एतद्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर एक सब्सिडीरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता और यह जांच करने के लिए कि क्या वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को समाप्त किए जाने से सब्सिडी के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, सीवीडी नियमों के नियम 24 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 9 के अनुसरण में एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. संबद्ध देश

19. वर्तमान जांच मलेशिया में विचाराधीन उत्पाद के कथित सब्सिडी प्राप्त करने के संबंध में है।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

20. जांच के लिए जांच की अवधि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 (12 माह) तक है। क्षति विश्लेषण जांच की अवधि में 2021-22, 2022-23 और 2023-24 और जांच की प्रस्तावित अवधि शामिल है।

ञ. प्रक्रिया

21. निर्णायक समीक्षा जांच में अधिसूचना सं. 6/13/2019-डीजीटीआर दिनांक 11.12.2020 के अनुसार प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी प्रवृत्त सब्सिडीरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति की संभावना का विश्लेषण भी करेंगे।
22. नियम 7,8,9,10,11,12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के प्रावधान अनिवार्य परिवर्तनों सहित वर्तमान समीक्षा में लागू होंगे।

ट. सूचना की प्रस्तुति

23. सभी पत्राचार ईमेल पते dd17-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, जिसके साथ ही एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्व योग्य पीडीएफ / एम एस वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फाइलें एम एस एक्सेल फॉर्मेट में हो।
24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध हैं उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रिया से अद्यतन और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से dd17-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए, जिसके साथ ही इसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल आवेदन का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा पाटनरोधी सीवीडी के नियम 7(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।
30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 7(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण का प्रदर्शन करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना को प्रस्तुत करना

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को सीवीडी नियमावली के नियम 8 तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक सूचना के अनुसार उसी का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
32. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
33. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होनी चाहिए जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा खाली रखा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उचित रूप से और पर्याप्त रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए जो उस सूचना पर निर्भर करता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।
35. अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, अपवाद की परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा नियमावली, 1995 के नियम 8 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के साथ कारणों का ऐसा विवरण कि ऐसा सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
36. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में इंगित किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
37. गोपनीयता के दावे पर नियम 8 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा उसके पर्याप्त और समुचित कारण विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।
39. प्राधिकारी, संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।
40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध के अगोपनीय पाठ तथा अन्य सारी जानकारी को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अथवा बाद में अलग से पत्राचार के माध्यम से प्रदान की गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

Newdelhi, the 24th June, 2025

Case No. CVD (SSR) 01/2025

Subject: Initiation of countervailing duty investigation concerning imports of Textured Tempered Coated and Uncoated Glass originating in or exported from Malaysia.

1. **F.No.7/10/2025-D.G.T.R.—** Borosil Renewable Limited (BRL) and Vishakha Glass Pvt. Ltd. (VGPL) (hereinafter referred to as the 'applicants' or the 'Domestic Industry') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority')

under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “CVD Rules” or the “Rules”) for the initiation of an extension and enhancement of countervailing duty investigation concerning imports of ‘Textured Tempered Coated and Uncoated Glass’ (hereinafter referred to as the “product under consideration” or the “subject goods” or the “PUC”) originating in or exported from Malaysia (hereinafter referred to as the “subject country”).

A. **BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATION**

2. The original Anti-Subsidy Investigation concerning imports of subject goods from subject country was initiated on 12.9.2019 by the Designated Authority vide its initiation notification No. 6/13/2019 DGTR. Pursuant to detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of subject goods from the subject country vide its final findings notification No.6/13/2019-DGTR dated 11.12.2020. The recommendations of the Designated Authority were implemented vide Notification No. 03/2021-Customs (ADD) dated 09.3.2021 for a period of five years. The current Anti-dumping duty is valid up to 08.03.2026.

B. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration in the present application is "Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “Product under Consideration”). The minimum level of transmission required in the subject good can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid. The glass whether coated or uncoated is tempered / toughened in a tempering furnace, as it is essential for solar applications. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Low Iron Solar Glass, Solar Glass Low Iron, Solar PV Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass etc.
4. The subject goods are used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid. The glass whether coated or uncoated is tempered / toughened in a tempering furnace as it is essential for Solar applications. The glass used in these applications as per current trend is from 2MM to 4 MM in thickness. Size of the subject goods depends upon the purpose and module size. The glass is cut in various sizes as per customer requirement before tempering as such or after coating. Since this is the sunset review investigation, the product remains the same as was defined by the Authority in the final findings.
5. The subject goods are classified under chapter heading 70071900. However, it has been claimed by the Domestic Industry that the subject goods are also being imported under various other tariff headings like 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 etc. It is clarified that the HS codes are only indicative, and the product description shall prevail in all circumstances.

6. The applicant has not proposed any PCN.
7. However, the parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation. Submissions made without justification will not be considered by the Authority.

C. LIKE ARTICLE

8. The applicants have submitted that subject goods produced by the applicant companies and the subject goods imported from the subject country are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject country and those produced by the applicants. Textured Toughened (Tempered) Glass produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country

D. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

9. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

“‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”

10. The application has been filed by M/s Borosil Renewables Limited (BRL) and M/s Vishakha Renewables Ltd. (VRL). Apart from the applicants, there are three other producers in India, viz. Gobind Glass & Industries Ltd, Triveni Renewables Pvt. Ltd., Gold Plus Float Glass Ltd., who had commenced production of the subject goods.
11. The applicants have certified that they have not imported the subject goods from the subject country. Moreover, the applicants are not related to any importer or exporter of the subject goods.
12. The investigating team is of the *prima facie* opinion that the applicant domestic producers constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the CVD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of Rule 6(3) of the CVD Rules, 1995

E. SUBSIDY PROGRAMS

13. The applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the government of different provinces and Municipalities in which producers/exporters are located, and other 'Public bodies. The applicants have relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain.
14. The prima facie evidence provided by the applicants show that the producers and exporters of the subject goods in Malaysia continued to benefit from a number of subsidies granted by the Government of Malaysia and/or other public bodies as listed below. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; Provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc.

I. Schemes Identified as Grants

- i. Subsidies in Natural Gas
- ii. The Market Development grant

II. Schemes Identified as Tax Incentive

- iii. Pioneer Status
- iv. Investment Tax Policies
- v. Reinvestment Allowance
- vi. Accelerated Capital Allowance
- vii. Green Financing Initiatives
- viii. Net Energy Metering (NEM) & Solar incentives
- ix. Regional Incentives (Sabha / Melaka).
- x. Supply Chain facilitation Program
- xi. Group Relief
- xii. Allowance Industrial Building (IBA)
- xiii. Allowance for plants and Machinery
- xiv. Double Deduction for Promotion of Malaysian brand
- xv. Incentive for manufacturing and manufacturing related service in East Cost Economic Corridor
- xvi. Draw back on Import duty, Sales tax and Excise duty
- xvii. Sales Tax Exemption
- xviii. Exemption from Import Duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activities
- xix. Exemption from Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables
- xx. Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment
- xxi. Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components
- xxii. Double Deduction for Promotion of Exports
- xxiii. Double Deduction for Promotion of Export Cargo
- xxiv. Allowance for Increased Export
- xxv. Tax Exemptions for Exporters in Free Trade Zones

15. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Governments of the subject country or other regional or local governments of such subject country, including public bodies and confer benefit on the recipient (s). They are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable. They are also in some cases alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance.
16. The producers/exporters are advised to provide information with respect to any other subsidy scheme that may have been availed by them. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of investigation.

F. LIKELIHOOD OF CONTINUATION / RECURRENCE OF SUBSIDY AND INJURY

17. There exists *prima facie* evidence indicating a likelihood of continuation or recurrence of subsidization and resultant injury to the domestic industry in the event of withdrawal of the anti-subsidy duty. This is based on factors such as the adverse price effects of such imports, including sales below the cost of production of the domestic industry, underutilization of production capacity, declining profitability, reduced return on capital employed, and the likely negative impact on the overall performance and viability of the domestic industry if the current anti-subsidy measures are discontinued.

G. INITIATION OF THE INVESTIGATION

18. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, based on the *prima facie* evidence submitted by the applicants, substantiating likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of anti-subsidy duty on imports of the subject goods from the subject country and to examine whether the expiry of the existing countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidy and consequent injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 of the Act, read with Rule 24 of the CVD Rules.

H. SUBJECT COUNTRY

19. The present investigation is in respect of alleged subsidization of the product under consideration in Malaysia.

I. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

20. The period of investigation for the purpose of the present application is January 2024 to December 2024 (12 months). The injury analysis covers the POI and 2021-22, 2022-23 and 2023-24.

J. PROCEDURE

21. The sunset review investigation will cover all aspects of Final Finding published vide Notification No.6/13/2019-DGTR dated 11.12.2020. The Authority will also undertake

likelihood analysis of continuation / recurrence of subsidization and injury in the event of expiry of anti-subsidy duty in force.

22. The provisions of Rules 7,8,9,10,11,12, 13, 18, 19, 20, 21 and 22 shall be mutatis mutandis applicable in this present review.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd17-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
24. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. TIME LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd17-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8 of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
32. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
35. The non-confidential summary must be insufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in this initiation notification.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request there in to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties.

N. **NON-COOPERATION**

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority